



राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र

# हलधर



Email id: haldharkisan@gmail.com

RNI NO. MPHIN/2022/85285

डाक पंजी. क्र. - MP/KDW/93/2023-24

वर्ष 02 अंक 9

नवंबर 2023

पृष्ठ- 8 मूल्य- 5.00 रुपए

# खेती और देशी प्रजातियों को प्रभावित कर रहे खतरनाक पौधे, 20 राज्यों में किये अध्ययन

एक नए अध्ययन में खुलासा हुआ है कि

भारत में प्राकृतिक आवासों को आक्रामक पौधों की प्रजातियों से भारी खतरा है। खेती और देशी प्रजातियों के लिए यह पौधे खतरनाक साबित हो रहे हैं। अध्ययन में कहा गया है कि, भारत में आक्रामक पौधों की प्रजातियों ने 22 प्रतिशत प्राकृतिक आवासों पर कब्जा किया है। यहां इनके 66 प्रतिशत प्राकृतिक आवासों तक पहुंचने की आशंका जताई गई है। यह अध्ययन 20 भारतीय राज्यों में 3,58,000 वर्ग किमी में फैले बाघों के आवासों पर आधारित है।

यह अध्ययन वन्यजीव संस्थान के दो वैज्ञानिकों निनाद अविनाश मुंगी और उमर कुंरेशी द्वारा किया गया है। अध्ययन के मुताबिक, जैविक आक्रमण से जैव विविधता और लोगों को खतरा है, जिससे भारत जैसे विकासशील उष्णकटिबंधीय देश अधिक असुरक्षित है।

जर्नल ऑफ एनवाइड इंकोलाजी में प्रकाशित पांच साल के लंबे अध्ययन में 3,58,550 वर्ग किलोमीटर को कवर करने वाले 1.58 लाख जमीनी हिस्सों का अध्ययन किया गया। साथ ही देश में 11 सबसे प्रचलित आक्रामक प्रजातियों का पता लगाया गया है। अध्ययन में कहा गया है कि नमूनों में 31 प्रतिशत सबाना, 51 प्रतिशत शुष्क पर्णपाती जंगल, 40 प्रतिशत नम पर्णपाती जंगल, 29 प्रतिशत अर्ध-सदाबहार जंगल, 44 प्रतिशत सदाबहार जंगल और 33 प्रतिशत सबाना नम घास के मैदान शामिल थे।

अध्ययन के मुताबिक, 22 प्रतिशत प्राकृतिक इलाकों में सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाले पौधों ने कब्जा किया है और ये 66 प्रतिशत प्राकृतिक क्षेत्रों को खतरों में डाल सकते हैं। अध्ययन में यह भी बताया गया है कि ये अनुमान सांख्यिकीय रूप से सटीक पाए गए हैं। अध्ययन में कहा गया है कि, आक्रामक प्रजातियों के कब्जे के लिए सबाना सबसे अधिक यानी 87 प्रतिशत उपयुक्त पाया गया, इसके बाद नम घास के मैदान और शुष्क पर्णपाती जंगल लगभग 72 प्रतिशत थे, जबकि सदाबहार जंगल अपेक्षाकृत 42 प्रतिशत यानी कम उपयुक्त पाए गए थे।

अध्ययन में शामिल 11 आक्रामक पौधों की प्रजातियों में लैटाना कैमारा को सबसे अधिक आक्रामक पाया गया, जो कब्जा किए गए प्राकृतिक आवास के लगभग 50 प्रतिशत के लिए जिम्मेवार है। अध्ययन में कहा गया है कि मिकानिया माइक्रंथा का विस्तार अपेक्षाकृत कम देखा गया और यह मुख्य रूप से नम घास के मैदानों और जंगलों में पाया गया था। अध्ययन में यह भी पाया गया कि, पशुओं को चराने और जलवायु परिवर्तन से प्रेरित कृषि जलवायु स्थितियों के रूप में मानवजनित गड़बड़ी ने आक्रामक प्रजातियों के फैलने को और सुविधाजनक बना दिया है। अध्ययन में कहा गया है कि आक्रामक प्रजातियों में मूल प्रजातियों पर कब्जा करने और प्राकृतिक चारे और आवास की गुणवत्ता को प्रभावित करने की क्षमता होती है। मानवजनित बदलावों से पूरे भारत में आक्रामक प्रजातियों की कब्जा करने की क्षमता में बढोतरी हुई है। अन्य पर्यावरणीय कारणों के प्रभाव को मोटे तौर पर

गंभीर सूखे से प्रभावित रहा भारत का 20 फीसदी क्षेत्र, अमेरिकी वेदर रिपोर्ट में किया दावा



सूखी और नमी वाली प्रणालियों में अलग किया जा सकता है। अध्ययन में कहा गया है कि पानी की निकटता शुष्क प्रणालियों के आक्रामक पौधों को सुविधाजनक बनाती है, जबकि आग की निकटता नमी वाली प्रणालियों के आक्रामक पौधों को सुविधाजनक बनाती है।

अध्ययनकर्ता ने कहा कि यह पहली बार है कि देशव्यापी सर्वेक्षणों के माध्यम से समस्या की भयावहता का दस्तावेजीकरण किया गया है। अध्ययन में भारी आक्रामक संभावित क्षेत्रों की पहचान की गई है और यह सरकार को उनसे निपटने के लिए नीतियां बनाने में मदद कर सकता है, क्योंकि उनमें पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करने की क्षमता है। अध्ययन में मध्य भारत और पश्चिमी घाट में सबसे अधिक आक्रामक प्रजातियां पाई गईं, जहां 2022 बाघ गणना के अनुसार, भारत के 3,682 बाघों में से लगभग आधे इन हिस्सों में रहते हैं। अध्ययन में कहा गया है कि, पर्यावरण मंत्रालय ने पहले ही बाघों के आवासों में आक्रामक प्रजातियों पर व्यापक परियोजना के साथ इसे एक साथ जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर आक्रामक पौधों की निगरानी लागू की है।

2018 में बाघों के आकलन के लिए किए गए सर्वेक्षणों का उपयोग करते हुए वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों ने पाया कि भारत के दो तिहाई प्राकृतिक क्षेत्र मानवजनित बदलावों के कारण कई पौधों के आक्रमण की जड़ में हैं। अध्ययन में कहा गया है कि भारतीय वनों में आक्रामक प्रजातियों के एकमुश्त प्रबंधन के लिए 13.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी, जो एक कठिन कार्य होगा और इसलिए जैव विविधता की बहाली को बढ़ाने के लिए कम से कम कब्जे वाले क्षेत्रों की पुनर्स्थापना को प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई है।

हलधर किसान नई दिल्ली। अमेरिका की राष्ट्रीय मौसम एजेंसी, नोआ ने वर्ष 2023 को वैश्विक स्तर पर अब तक का सबसे गर्म साल बताते हुए कहा है कि भारत में कम से कम 20 प्रतिशत क्षेत्र अभी गंभीर सूखे की चपेट में फंसा हुआ है।

मौसम एजेंसी के मुताबिक इंडिया ड्राइट मॉनिटर पर इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि भारत के उत्तरी, पूर्वी एवं दक्षिण-पश्चिमी तटीय भाग में सूखे की स्थिति बनी हुई है और इस तरह देश का लगभग 21.6 प्रतिशत हिस्सा सूखे की चपेट में है।

इससे भारत में गहरी चिंता उत्पन्न हो गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ( आईएमडी) के आंकड़ों से पता चलता है कि अक्टूबर के आरंभ से अब तक देश के एक तिहाई से अधिक भाग में बारिश का भारी अभाव देखा जा रहा है। नोआ का आंकड़ा 13 अक्टूबर तक का है। नोआ के अनुसार सितंबर के बहुत विशाल क्षेत्र में सामान्य स्तर से ज्यादा शुष्क एवं गर्म मौसम रहा। सितंबर में औसत वैश्विक तापमान 20 वीं शताब्दी के औसत स्तर 15 डिग्री सेल्सियस से 1.44 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। अमेरिका की एक अन्य एजेंसी के अनुसार इस बात के 99 प्रतिशत से ज्यादा आसार हैं कि 2023 का साल विश्व पर अब तक का सबसे गर्म वर्ष साबित हो सकता है। सितंबर का महीना पिछले 174 वर्षों में सबसे गर्म रहा। दुनिया के कई भागों में कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्र प्रभावित हुआ। वहां कम बारिश होने से पानी का संकट बढ़ गया और खेतों की मिट्टी सूख गई। सभी महाद्वीपों में इससे कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ा है। लगातार छठे माह सितंबर में विश्व स्तर पर महासागरों की सतह का मासिक तापमान रिकॉर्ड ऊंचे स्तर पर बरकरार रहा। अगस्त में यह सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा था। उस समय भारत सहित कई देशों में बारिश का भारी अभाव रहा। ऑस्ट्रेलियाई मौसम ब्यूरो ने भी कुछ इसी तरह का अनुमान लगाया है। उसका कहना है कि अप्रैल-सितंबर 2023 की छमाही के दौरान वैश्विक स्तर पर समुद्र की सतह का तापमान अब तक का सबसे ऊंचा रहा। प्रशांत महासागर के उत्तरी, पश्चिमी एवं दक्षिणी-पश्चिमी भाग के साथ-साथ अटलांटिक महासागर एवं हिन्द महासागर में भी समुद्र की सतह का तापमान काफ़ी यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के लिए इस बार सितंबर का महीना सबसे ज्यादा गर्म रहा जबकि एशिया में यह दूसरा एवं ऑस्ट्रेलिया में तीसरा सबसे गर्म महीना साबित हुआ।

## एजेंसी देना है-

प्रतिष्ठित मासिक समाचार पत्र हलधर किसान कृषि क्षेत्र से जुड़े शोध, अनुसंधान, नई तकनीक, योजनाओं के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के समावेश के साथ नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है। अखबार की प्रतियां नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए वार्षिक सदस्यता लेने, एजेंसी/ विज्ञापन प्रकाशन के लिए हमारे वाट्सअप नंबर (88174 02860) या हमारे प्रधान कार्यालय 598, वेगास मॉल, कोर्पोरेट बिल्डिंग, एस.14 द्वारका साउथ वेस्ट, नई दिल्ली 110075 या मप में 762, बीज भंडार भवन, न्यू नूतन नगर खरगोन में संपर्क कर सकते हैं।

नोट: कृषि, उद्योगिकी, मछलीपालन, ऊर्जा, पर्यावरण जैसे विषयों पर लिखेलेख प्रकाशन के लिए भी वाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं। आपके द्वारा भेजे गए लेख, शोधकार्य या कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकी, सफलता हासिल करने संबंधित समाचार का भी प्रमुखता से प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे।

# जलवायु परिवर्तन में भी चने की ये तीन किस्में देगी बेहतर उपज



88174 02860

विश्व की 67 प्रतिशत चने की पैदावार होती है। भारत में चने का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में होता है। ऐसे में किसान चने की कम लागत में अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से स्वेती कर अधिक लाभ कमा सकते हैं। तबीजी फार्म के उपनिवेशक कृषि मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि चने के लिए लवण व क्षार रहित, जल निकास वाली उपजाऊ भूमि उपयुक्त रहती हैं। चने की बुवाई का उपयुक्त समय मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर हैं। उन्होंने बताया कि चने की फसल को कीट एवं रोगों से बचाकर उत्पादन एवं उत्पादकता में बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके लिए किसानों को बीजोपचार एवं रोग प्रतिरोधक किस्मों का प्रयोग करना चाहिए।

कार्यालय के कृषि अनुसंधान अधिकारी डॉ. जितेन्द्र शर्मा ने बताया कि चने की फसल में जड़ गलन एवं सूखा जड़ गलन एवं उकठा जैसे हानिकारक रोगों का प्रकोप होता है। इन रोगों से बचाव के लिए ट्राईकोडर्मा से भूमि उपचार करना चाहिए। भूमि उपचार करने के लिए बुवाई से पूर्व 10 किलो ट्राईकोडर्मा को 200 किलो आद्रता युक्त गोबर की खाद में मिलकर 10.15 दिन छाया में रखें। इस मिश्रण को बुवाई के समय प्रति हेक्टेयर की दर से पलेवा करते समय मिट्टी में मिला दें साथ ही रोग प्रति रोधी किस्मों का उपयोग करें। इसके साथ ही बीजों को 1 ग्राम कार्बेन्डाजिम एवं थ्रीम 2.5 ग्राम या ट्राईकोडर्मा 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बुआई करें।

चने की फसल में दीमक, कटवर्म एवं वायर वर्म की रोकथाम के लिए क्यूलानफॉस 1.5 प्रतिशत चूर्ण 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से आखिरी जुलाई से पूर्व छिड़काव करें। चने की फसल में दीमक से बचाव के लिए बीजों को फिप्रोनिल 5 एससी 10 मिली या इमीडाक्लोप्रिड 600 एफएस का 5 मिली प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार कर बुवाई करें।

जलवायु परिवर्तन के जोखिम को कम करने के लिए जलवायु अनुकूल खेती एक बेहतर विकल्प है। जलवायु ऐसा फैक्टर है जिसका प्रभाव जीव,जंतु,पौधे,पौधों और खेती पर होता है।कृषि शोध संस्थान जलवायु परिवर्तन के जोखिम को कम करने के लिए फसलों की नई किस्में विकसित कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया में पहले से ही तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है, इसलिए गर्मी और सूखा से सहनशील चने की किस्में भारतीय किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती हैं। आईसीआरआईएसएटी के सहयोग से आईसीएआर के संस्थानों ने तीन नई चने की किस्में विकसित की हैं, जो



जलवायु, लचीली और रोग प्रतिरोधी हैं और इन किस्मों की खासियतों को जानते हैं।

## चने की नई किस्मों की खेती करें किसान

बदलते जलवायु परिवर्तन के हिसाब से जलवायु अनुकूल चने की सूखा सहने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता और अधिक उपज देने वाली चने की तीन नई किस्में विकसित की गई हैं। इन किस्मों को भारतीय किसानों के लिए साल 2021 में केंद्रीय किस्म विमोचन समिति द्वारा खेती के लिए अधिसूचित किया गया थाण् कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक, भारत के चना उत्पादक क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन और सूखे के कारण चने की उपज सालाना 60 फीसदी तक घट जाती है। बदलती जलवायु परिस्थितियों में चने तीन नई किस्में आईपीसीएल 4.14, पूसा 4005 और समृद्धि किसानों के लिए बेहतर उपज दिला सकती हैं। वर्षा आधारित क्षेत्र हो या सिंचाई क्षेत्र, दोनों जगहों में ये किस्में बढ़ते तापमान और सूखे की परिस्थितियों में बेहतर उत्पादन दे सकती हैं।

## सूखे में भी ये किस्म देगी अधिक उपज

आईपीसीएल 4.14 चने की किस्म साल 2021 में रिलीज की गई थी और इस किस्म को भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर द्वारा विकसित किया गया हैण् इसका प्रति एकड़ उत्पादन 7 से 8 क्विंटल होता है। यह किस्म 128 से 133 दिनों में तैयार हो जाती है। इस किस्म को भारत में चने की खेती को प्रभावित करने वाली जलवायु परिस्थितियों और अन्य कारकों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए विकसित किया गया है। इस किस्म की खेती से वातावरण में सूखे की स्थिति में बेहतर उत्पादन मिल सकता है। इस किस्म को पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर के मैदानी इलाकों, राजस्थान के कुछ हिस्सों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया गया है। यह स्तिंचित और समय पर बुवाई के लिए बेहद बेहतर किस्म है। यह किस्म विल्ट, कॉलर रोट, स्टंट रोगों के प्रति मध्यम रूप से प्रतिरोधी

और शुष्क जड़ सड़न के प्रति मध्यम रूप से सहनशील है।

## पूसा 4005 जलवायु चुनौती में भी बेहतर

पूसा 4005, यानी बीजीएम 4005, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित गई है और इसे 2021 में खेती के लिए जारी किया गया था। इसकी उपज क्षमता सूखे को परिस्थितियों में प्रति एकड़ 8 क्विंटल होती है। यह किस्म लगभग 130 से 131 दिनों में तैयार हो जाती है। इस किस्म को भारत में चने की खेती को प्रभावित करने वाली जलवायु परिस्थितियों और अन्य कारकों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए विकसित किया गया हैण् इस किस्म को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया गया है। यह किस्म विल्ट यानी उकठा रोग, कॉलर रोट, स्टंट रोगों के प्रति मध्यम रूप से प्रतिरोधी है और शुष्क जड़ सड़न के प्रति मध्यम रूप से सहनशील है।

## समृद्धि किस्म इन राज्यों के लिए बेहतर

समृद्धि 19.3 देसी किस्म है, जिसे भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर ने विकसित किया है। इसे 2021 में किसानों के लिए खेती के लिए जारी किया गया थाण् यह उकठा रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म है और स्तिंचित स्थिति में खेती के लिए बेहतर है। इसकी उपज क्षमता प्रति एकड़ 8 से 9 क्विंटल है। इस किस्म की खेती मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए बेहतर है। यह किस्म 100 से 110 दिनों में पककर तैयार हो जाती है।

## चने की बुवाई के समय इन बातों का रखें ध्यान

चने की बुवाई का सर्वोत्तम समय 15 से 30 अक्टूबर तक है। निचले क्षेत्रों में चने की बुवाई नवंबर में करनी चाहिए। चने की खेती चिकनी दोमट या बारीक दोमट मिट्टी वाले खेतों में करनी चाहिए। सीड ड्रिल से 6 से 8 सेमी. गहराई पर बोनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी 30 से 45 सेमी होनी चाहिए। चने की बुवाई के लिए छोटे आकार की किस्म का बीज दर 26 किलोग्राम, मध्यम आकार के चने की किस्म का बीज दर 30 किलोग्राम और बड़े दाने वाली किस्म का बीज दर 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोना चाहिए।

## चने का बीज बोने से पहले बीज का उपचार करना न भूलें

चने का बीज बोने से पहले बीज का उपचार करना न भूलें, क्योंकि इसमें उकठा रोग, रतुआ रोग, शुष्क जड़ रोग का प्रकोप अधिक होता है। इसलिए बीज बोने से पहले बीज का उपचार करें। चने के उकठा रोग और गलन रोग की रोकथाम के लिए 2.5 ग्राम थ्रीम या 1 ग्राम बाविस्टिन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। कीटों से रोकथाम के लिए क्लोरपाइरीफास 1 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। इसके बाद चने की अधिक पैदावार के लिए राइजोजिनियम कल्चर से उपचारित करें। 200 ग्राम कल्चर का एक पैकेट 10 किलोग्राम बीज उपचार के लिए पर्याप्त है। कल्चर को बाल्टी में घोलकर 10 किलो बीज डालकर अच्छी तरह मिला लें ताकि सभी बीज अच्छी तरह मिल जाण् कुछ समय बाद चने की बुवाई करनी चाहिए।

# दिसंबर में आयोजित किया जाएगा कृषि कुभाए किसानों को बताई जाएगी देश विदेश की तकनीके

**हालधर किसान।** उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस वर्ष कृषि कुंभ 2.0 का आयोजन करने जा रही है। जिसको लेकर यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शर्मा ने बताया कि दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में होने वाले कृषि कुम्भ को ऐतिहासिक और तकनीकी रूप से सशक्त किया जाएगा। जिसमें तमाम कृषि संगठन हिस्सा लेंगे, जो अपने अपने देश की तकनीक बताएंगे। आयोजन का उद्देश्य प्रदेश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डालर के स्तर पर ले जाने के लिए किसानों को उत्पादक से उद्यमी बनाना, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर पोषण, पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के साथ/साथ भविष्य की जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने की तैयारी है। खेती की लागत कम करने, किसानों की आय बढ़ाने और स्वास्थ्य तथा पोषण की दृष्टि से श्री अन्न को बढ़ावा देना है। इसे एक ग्लोबल इवेंट की तरह आयोजित किया जाएगा। कृषि कुम्भ में 19 सत्र होंगे, जिसमें देश/विदेश के वैज्ञानिक तकनीक बताएंगे। अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के भी स्टॉल लॉगेंगे। सरकार की कोशिश है कि इसमें 500 संगठन हिस्सा लें। इसमें डिजिटल कृषि, उद्यान को बढ़ावा, गन्ना, पशु धन और चारा उत्पादन पर भी चर्चा होगी। वहीं प्रोसेसिंग इकाई का भी प्रदर्शन होगा। शाही ने कहा कि श्रीअन्न उत्पादन में प्रतिस्पर्धा बढ़ने, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किसानों को जागरूक करने, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और किसानों को उद्यमी बनाने को लेकर चर्चा होगी। कब आयोजित किया जाएगा कृषि कुम्भ 2023 कृषि मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि कुंभ का द्वितीय संस्करण ( अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी एव सम्मेलन ) का आयोजन इस वर्ष दिसंबर के द्वितीय पखवाड़े यानि की 15 दिसंबर के बाद किया जाएगा। यह कार्यक्रम भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान तेलीबागए लखनऊ के परिसर में आयोजित होगा। कृषि मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि दिसंबर में आयोजित होने वाला यह कृषि कुंभ 4 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा। इस बार का कुंभ पिछले कृषि कुंभ 2018 के मुकाबले अधिक भव्य और दिव्य बनाने की सरकार की योजना है ताकि किसान तकनीक तरक्की की ओर बढ़ सकें।

# मोजाबिक से तुअर दाल की आपूर्ति में जुटी सरकार केंद्र ने उच्चायुक्त से कि व्यापारिक मुद्दे पर चर्चा

जानकारी दी तथा इनकी शीघ्र मंजूरी की आवश्यकता पर बल दिया। इस बात पर भी जोर दिया गया कि तुअर के व्यापार के लिए द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन को बरकरार रखने की जरूरत है, क्योंकि यह दोनों देशों के उत्पादकों और उपभोक्ताओं के प्रति भारत और मोजाबिक की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उच्चायुक्त महामहिम एमिंडो, पेररिया ने मोजाबिक में समग्र कृषि इकोसिस्टम के लिए भारत और मोजाबिक के बीच व्यापार संबंधों के महत्व पर जोर दिया।

## हर साल 30 लाख टन तक दालों का होता है आयात

उन्होंने आश्वासन दिया कि तुअर व्यापार से संबंधित मौजूदा मुद्दों को हल करने और मोजाबिक से भारत में तुअर निर्यात के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव और मोजाबिक के उच्चायुक्त के बीच इस समय हुई बैठक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोजाबिक से आयात के सुचारू प्रवाह से आने वाले महीनों के दौरान तुअर की उपलब्धता बढ़ेगी और भारतीय उपभोक्ताओं के लिए उपलब्धता तथा इसका किफायती होना सुनिश्चित होगा। घरेलू बाजार में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत में प्रत्येक वर्ष 2.5-30 लाख टन तक दालों का आयात किया जाता है।।

**हालधर किसान (88174 02860)** | घरेलू बाजार में तुअर दाल के बढ़ते दामों पर नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने मोजाबिक से दालों खरीदों लेकिन व्यवधानों के कारण निर्यात में देरी हो रही है। इस स्थिति के जवाब में केंद्र ने मोजाबिक सरकार से बंदरगाह प्रक्रियाओं को शीघ्रता से पूरा कर दाल की खेप भेजने का आह्वान किया।

उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव ने मोजाबिक, बंदरगाहों पर प्रतीक्षारत तुअर निर्यात खेपों की शीघ्र निकासी पर जोर दिया भारत में उपभोक्ताओं के लिए तुअर की उपलब्धता और इसके किफायती होने को सुनिश्चित करने के लिए तुअर की उपलब्धता बढ़ाने की मंजूरी दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने मोजाबिक के उच्चायुक्त महामहिम एमिंडो, पेररिया के साथ तुअर से संबंधित व्यापार और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक की। जुलाई 2023 से मोजाबिक में पैदा हुई प्रक्रियात्मक बाधाओं पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इसके कारण देश से तुअर निर्यात खेप को भेजने में देरी हो रही है। उन्होंने उच्चायुक्त से मोजाबिक से तुअर के निर्बाध निर्यात को सुनिश्चित करने के लिए ठीक उस रूप में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया, जैसा भारत सरकार ने आयात को सुचारू और निर्बाध बनाने के लिए आवश्यक नीतिगत उपाय किए हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव ने महामहिम एमिंडो, पेररिया को मोजाबिक बंदरगाहों पर मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहे तुअर निर्यात खेप के बारे में



# अच्छी खबर: प्रदूषण नहीं अब पैसा कमाकर देगी पराली, यूपी में तैयार हो रहा ग्रीन एनर्जी प्लांट



8817402860 . उत्तर प्रदेश के

किसानों के लिए राहत भरी खबर है। बुलंदशहर में में पराली से कंप्रेस्ड गैस (सीएनजी) का उत्पादन होगा, जिससे आर के साथ. साथ बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके साथ ही शुद्ध जैविक खाद (ग्रीन एनर्जी) का भी उत्पादन होगा, जिसके इस्तेमाल से होने वाली पैदावार के सेवन से बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सकेगा। वहीं खेतों में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से जल्द निजात मिलेगी।

सीएम योगी ने प्रदेश में जैव ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए जैव ऊर्जा नीति 2022 को जारी किया था। इस नीति के तहत बड़े पैमाने पर निवेश का लक्ष्य रखा गया था। कई बड़े निवेशकों ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रदेश सरकार के साथ एमओयू किया था, जो अब धरातल पर उतरने जा रहा है। योगी सरकार ने हर तहसील में बायोगैस

पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता भी होगी कम, मिलेगा रोजगार



प्लांट का लक्ष्य रखा था, जिसमें से कुछ जल्द ही शुरू होने का तैयार है। **जैविक खाद के उत्पादन से शुद्ध होगा खानपान**

उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात ये ही है कि इसमें बड़ी मात्रा में जैविक खाद का उत्पादन होगा। कंप्रेस्ड गैस के उत्पादन में जो वेस्ट निकलेगा वो 100 प्रतिशत जैविक होगा। यह वेस्ट सॉल्लिड भी होगा और लिक्विड भी। जो लिक्विड जैविक खाद होगी प्लांट की ओर से उसे 3 साल तक किसानों को मुफ्त दिया जाएगा। इन किसानों को डीएम या सीडीओ विहित करेंगे। इससे उन किसानों को फायदा होगा जो फर्टिलाइजर, डीएपी, यूरिया नहीं खरीद पाते हैं।

जैविक खाद और लिक्विड खाद का ये फायदा है कि खेती उपजाऊ जमीनों में फर्टिलाइजर खादों की एक मोटी लेयर बिछ चुकी है। वह पड़ पौधों की जड़ों तक पहुंचने में समय लेती है। वहीं, जैविक खाद को इसमें डालेंगे तो यह 2 से 3 घंटे में जड़ तक पहुंच जाएगा। इससे किसानों का तो फायदा होगा ही, साथ ही आम लोगों को भी शुद्ध जैविक पूरू मिल सकेगा। शुद्ध खान-पान से लोगों की सेहत को फायदा होगा।

## 3 टन सीएनजी का उत्पादन होगा

जो प्लांट शुरू होने को तैयार है उनमें बुलंदशहर का बुलंद बायोगैस भी है, जिसकी स्थापना ग्राम लौहगला तहसील में हो रही है। बुलंद बायोगैस ने प्रदेश सरकार के साथ 18.75 करोड़ रुपये का एमओयू किया था, जिसकी कोस्ट बढ़कर अब 21 करोड़ रुपये हो गई है। यह प्लांट दिसंबर में अपना उत्पादन शुरू कर देगा। इस प्लांट से प्रतिदिन 3 टन सीएनजी का उत्पादन होगा, जिससे प्रदेश में पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम होगी। वहीं 80 से 100 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इनमें स्क्रिड और अनस्क्रिड दोनों तरह के लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। बुलंद बायोगैस के ओनर अतहर अहमद ने बताया कि प्लांट में सिर्फ पराली ही नहीं, बल्कि पुआल, गोबर, भूसा, गन्ने की मैली, म्यूनिसिपल वेस्ट जैसे डिग्रेडेबल वेस्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस या ये कहें कि सारी गैसों का मिक्सचर बनता है। इसको टेकनोलॉजी की मदद से सीएनजी को थूरीफाई किया जाता है। इस प्लांट के लिए इंडियन ऑयल से लाइसेंस मिल चुका है।

## श्री अन्न महोत्सव: सीएम योगी बोले, वैश्विक खाद्यान संकट के वक्त श्री अन्न बनेगा सहारा



### 35 कृषक उत्पादक संगठनों को सम्मानित किया

मुख्यमंत्री ने समारोह के दौरान श्री अन्न के क्षेत्र में कार्य करने वाले 35 कृषक उत्पादक संगठनों को सम्मानित किया। इसके अलावा प्रदेश के पांच कृषि विज्ञान केंद्रों (झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर और गाजीपुर) को मिलेट्स प्रसंस्करण संयंत्र के लिए 95.95 लाख की सहायता प्रदान की गई। साथ ही जिन कृषक उत्पादक संगठनों ने अधिक से अधिक किसानों को मिलेट्स फार्मिंग के लिए प्रशिक्षित और प्रोत्साहित किया उन्हें भी मुख्यमंत्री ने समारोह के दौरान सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, एमएसएमई मंत्री रमेश सचान, कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलाख, यूपी कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कैप्टन विकास गुप्ता, कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह, संजय अग्रवाल, डॉ देवेश चतुर्वेदी सहित कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए कृषक उत्पादन संगठनों और कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारीगण के अलावा बड़ी संख्या में प्रगतिशील किसान मौजूद रहे।

योगी ने कहा कि पिछली सदी के छठे और सातवें दशक तक बड़ी मात्रा में मोटे अनाज का उत्पादन होता था। ये हमारे दैनिक जीवन का अंग था। मगर बढ़ती आबादी की आवश्यकता और इस दिशा में शोध और अनुसंधान की गति धमने के कारण इसका उत्पादन कम होता गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केमिकल फर्टिलाइजर के अत्यधिक उपयोग से तमाम रोग बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि श्री अन्न का उत्पादन कम पानी वाले क्षेत्रों में भी होता है। हमें इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए इस दिशा में व्यापक पैमाने पर शोध और अनुसंधान की आवश्यकता है। ये खुशी की बात है कि आज हर परिवार में श्री अन्न का किसी ना किसी रूप में प्रयोग होना शुरू हो गया है। अब इस दिशा में व्यापक रूप से प्रयास प्रारंभ हुआ है।

हलधर किसान. लखनऊ.

8817402860

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंद्रा गांधी प्रतिष्ठान में राज्यस्तरीय श्री अन्न प्रदर्शनी एवं कार्यशाला के शुभारंभ समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि श्री अन्न का महत्व वैदिक काल से रहा है। भविष्य में भी जब दुनिया खाद्यान संकट का सामना करेगी तो श्री अन्न की उपयोगिता बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश श्री अन्न के उत्पादन का केंद्र बन सकता है। सीएम योगी ने इससे पहले तीन दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ करते हुए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए श्री अन्न उत्पादकों की ओर से लगाये ये प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल ने हमें बड़ा सबक दिया है। हम जितना कृत्रिम जीवन जीने का प्रयास करेंगे, महाभारियां हमें उताना ही परेशान करेगी। हमें प्राकृतिक वास और जीवमण्डली को अपनाना होगा और उसमें श्री अन्न बहुत ही सहायक होगा। इसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए शोध और अनुसंधान की आवश्यकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान के लिए कार्य कर रही उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के 34वां स्थापना दिवस पर अगले तीन दिन तक श्री अन्न महोत्सव का आयोजन हो रहा है। ये महोत्सव यूपी के किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का माध्यम बनेगा। सीएम

हलधर किसान (झारखंड)।  
8817402860

झारखंड राज्य कोडरमा जिले के डोमचांच में आलू की बेहतर पैदावार होती है। इसे देखते हुए बाजार समिति में आलू चिप्स प्लांट लगाए जाने की तैयारी हो रही है।

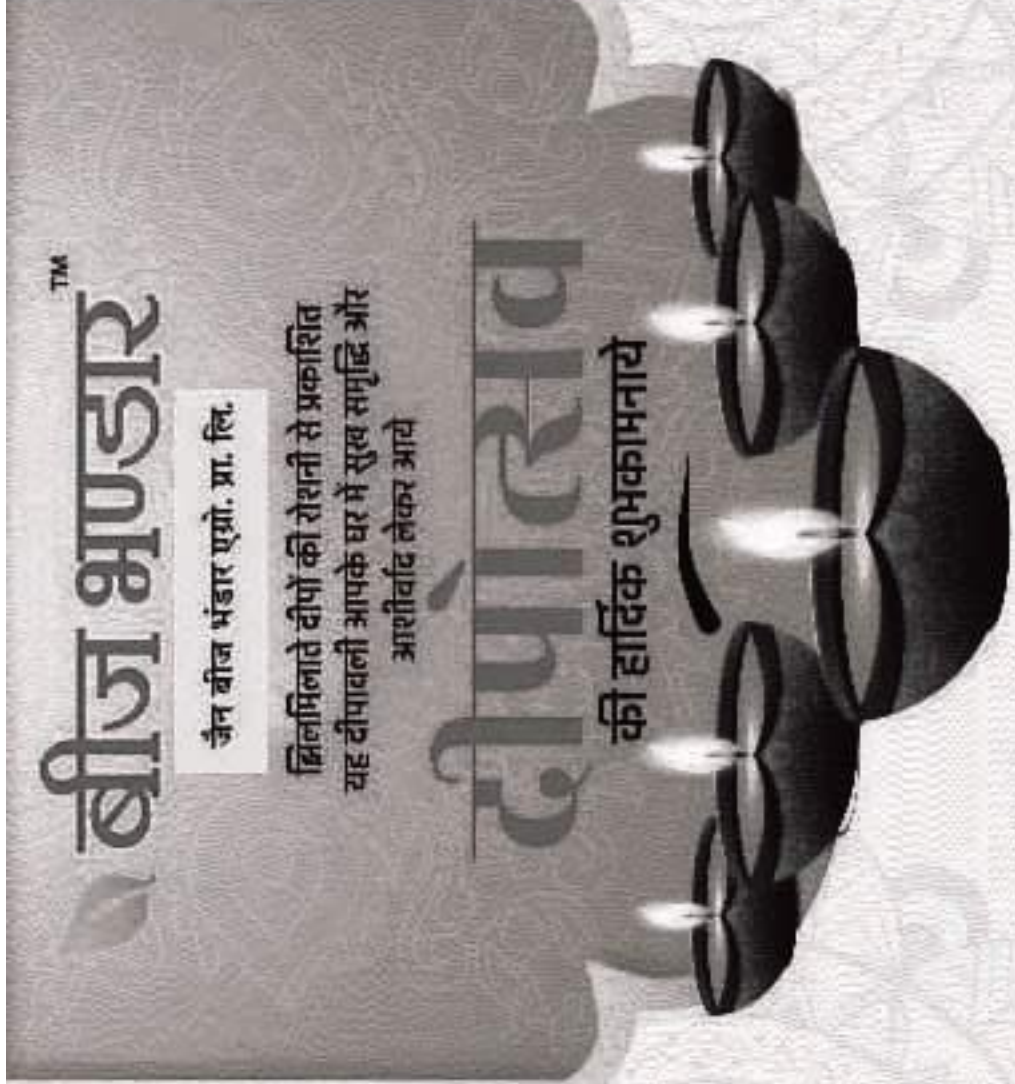
उपायुक्त मेधा भारद्वाज ने बताया आलू चिप्स प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है और जल्द ही शुभरी तिलैया स्थित बाजार समिति परिसर में खाली पड़े भूभाग पर मशीनें लगाई जाएंगी। आलू चिप्स के लिए फुलवर्धिया में सोना प्रजाति के आलू की खेती के लिए किसानों को प्रेरित और प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस आलू चिप्स प्लांट से 500 किसान सीधे तौर पर जुड़ेंगे,

## झारखंड के कोडरमा में लगेगा आलू चिप्स का प्लांट, 500 किसानों को होगा सीधा लाभ

जिससे न सिर्फ उनके आर्थिक उपार्जन में बढ़लाव आएगा, बल्कि कोडरमा के बने आलू चिप्स अब बाजारों में विभिन्न ब्रांडों को टक्कर भी देते नजर आएंगे।

आलू चिप्स प्लांट का संचालन एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा और इसमें किसानों के साथ साथ आजीविका महिला मंडल की सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। उपायुक्त मेधा भारद्वाज ने कहा कि आलू प्लांट लगाने को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है और जल्द ही जस्ट प्रोसेसिंग यूनिट बाजार समिति परिसर में स्थापित किया जाएगा, ताकि किसानों और आजीविका महिलाओं को रोजगार के साथ साथ बेहतर आर्थिक उपार्जन पर लाभ मिल सके।





धर्मन्द्र गिवारे  
स्वरगोन



रितेश कुशवाह  
धामनोद



कैलाशचंद्र कुशवाह  
कसरोवद



मोहन परमार  
अंजड



कमलेश पाटीदार  
मंडलेश्वर



प्रितम लोधी  
इंदौर



सुनील हम्मड  
कुशी



विरेंद्र पंवार  
मनावर



बाबुलालजी बर्फा  
राजपुर



दीपक जैन  
जबलपुर



कुंदन राजपुत  
खंडवा



जीतेन्द्र मंडराह  
छिन्दवाडा



सुधीर पाटीदार  
महु



केशरसिंह परिहार  
पुजापुरा



गौरव चावडा  
कालापीपल



# पारंपरिक खेती के साथ इस तरह की खेती से ले सकते हैं ज्यादा मुनाफा

**हलधर** **किसान**  
88174 02860

सहफसली योजना खेती के साथ किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में कारगर सिद्ध हो रही है। एक ही खेत में एक से अधिक फसलें पुरानी परंपरा है। जैसे गेहूँ चना एक साथ उगाना। मुख्य फसल की दो पंक्तियों के बीच में जल्दी पकने और बढ़ने वाली धनी फसलें बोई जा सकती हैं। स्तंभ आकार औषधि पौधे जो बड़े हैं उनके नीचे बेल वाली जैसे करेला और पहुंच आदि की फसलें लगा सकते हैं। छाया की आवश्यकता वाली फसलें अदरक सफेद मूसली अश्वगंधा हल्दी आदि लगाकर अधिकतम भूमि का प्रयोग करके उत्पाद की गुणवत्ता के साथ साध शुद्ध लाभ बढ़ाया जा सकता है। किसी कारणवश एक फसल खराब भी हो जाए तो उसके नुकसान की भरपाई दूसरी उपाय से हो सकती है। अतः जहां तक संभव हो सहफसल खेती किसानों को लगाना चाहिए। आजकल किसान गन्ने के साथ सहफसली खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं।

किसान लगातार पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं, जिसमें



## वया है सहफसली खेती?

सहफसली खेती एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से एक ही खेत में दो फसलें उगाई जाती हैं। इस तकनीकी से खेतों में दिए जाने वाले मुख्य फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से ही सहफसली के पौधे अपने लिए आपूर्ति कर लेते हैं।

## अनाज फसल की खेती

सहफसली की खेती में तिलहन और सब्जी फसल को उगा सकते हैं। सहफसली को उगाने के लिए एक अनुपात में उगाना चाहिए। जैसे गेहूँ की फसल के साथ सरसों। इसके लिए 9 गेहूँ की लाइन के बाद एक सरसों की लाइन होनी चाहिए। वहीं मक्का के साथ पत्ता गोभी के लिए 1 : 1 के अनुपात में लगा सकते हैं।

वह एक समय में एक ही फसल को उगाने रहे हैं। इससे किसानों को एक ही फसल पर हुआ खर्च ब लागत ही मिल पाती है। कभी-कभी तो मौसम की विषम परिस्थितियों के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इससे किसानों को आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है।

इन्होंने समस्याओं को देखते हुए किसानों का सहफसली खेती की ओर रुझान बढ़ा है, जिससे किसान एक खेती

के खर्च में दो फसलों का मुनाफा कमा रहे हैं। यदि आप भी सहफसली खेती करने चाहते हैं तो आपको फसलों के चयन में कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। मुख्य फसलों की दो पंक्तियों के बीच में जल्दी पककर तैयार होने वाली फसलें बोई जा सकती हैं।

## व्यापारिक फसल की खेती

सहफसली खेती के लिए गन्ना, सब्जियां और कई तरह की औषधीय फसलें शामिल हैं, जिन्हें सहफसली के रूप में उगाकर कमाई कर सकते हैं। जैसे गन्ने के साथ मटर और आलू जैसी सब्जी फसल उगा सकते हैं।

## दलहनी फसल की खेती

सहफसली की खेती में दलहनी फसल बेहद फायदेमंद होती है। क्योंकि दलहनी फसलों को सहफसली के रूप में उगाने से पौधों को उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन मिलती रहती है। इस वजह से दलहनी फसलों को लागभग सभी फसलों के साथ उगाना फायदेमंद होता है।

## सब्जी फसल की खेती

सहफसली खेती करने के लिए लता वाली सब्जी फसल को क्यारी बनाकर उगाने में बैंगन और टमाटर जैसी फसल को उगा सकते हैं। गेहूँ और सरसों की फसल के साथ आलू की फसल को उगा सकते हैं। सरसों की खेती में 3रू:1 के अनुपात में आलू को उगा सकते हैं।

## मसाला फसल की खेती

मसाला फसलों की भी सहफसली खेती की जा सकती है। जैसे आलू के साथ लहसुन को उगाना जा सकता है। इसके अलावा प्याज के साथ लहसुन और गन्ने के साथ धनिया को उगाना जा सकता है।

# खाद्य पदार्थों की हानि और बर्बादी को कम करना हमारी जिम्मेदारी: राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे



**हलधर** **किसान** (नई दिल्ली)।  
88174 02860

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण

राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने नई

दिल्ली के साउथ एंशियन रिजन में फूड

लॉस एंड वेस्ट प्रोक्शन विषय पर

अयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का

उद्घाटन किया। इस अंतर्राष्ट्रीय

कार्यशाला का आयोजन भारतीय कृषि

अनुसंधान परिषद और जर्मनी के थुनेन

संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान

परिषद के उप महानिदेशक एमआरएम,

डॉ. एस्के चौधरी, जर्मनी के थुनेन

इंस्टीट्यूट के अनुसंधान निदेशक डॉ.

स्टीफन लॉग, भाकेंअनुप के उप

महानिदेशक डॉ. एसएन झा और भारत,

बॉस्लादेश, भूटान, फ्रांस, जर्मनी,

इंडोनेशिया, नेपाल और श्रीलंका के

लगभग 120 प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सुश्री शोभा करंदलाजे ने किसानों और

उपभोक्ताओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण सामाजिक और

आर्थिक मुद्दे को हल करने के लिए आईसीएआर और

जर्मनी के थुनेन इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए प्रयासों की

सराहना की। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में लगभग 3

बिलियन टन खाद्य पदार्थों की बर्बादी होती है। विकसित

और विकासशील देशों की उपयुक्त प्रौद्योगिकियों और

## भारत में हर साल लगभग 74

## बिलियन टन खाद्य पदार्थों की हानि

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एजीजी डॉ. के

नरसेया ने खाद्य पदार्थों की हानि के ऐतिहासिक

परिश्रय पर एक परिचयात्मक प्रस्तुति दी। सभी

प्रतिनिधियों ने इस सत्र के दौरान परिवारों, कार्यलयों,

उद्योगों, समाज और समुदायों में खाद्य पदार्थों की हानि

और बर्बादी को रोकने की राय ली। यह समझते हुए

कि प्रचुर मात्रा में कृषि उत्पादन के बावजूद, उत्पादन से

लेकर खपत तक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में पर्याप्त मात्रा

में खाद्य पदार्थों की हानि हो जाती है या बर्बादी हो जाती

है। भारत में हर साल लगभग 74 बिलियन टन

खाद्य पदार्थों की हानि हो जाती है। अगर इस हानि को

रोका जाये, तो इससे काफी लोग लाभान्वित होंगे।

व्यावहारिक अनुभव के वैश्विक आदान प्रदान को

बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। भारत सरकार

खाद्य पदार्थों की हानि और बर्बादी को रोकने के लिए

व्यापक स्तर पर और सहयोगी प्रयासों को शुरू करने

में सभी पड़ोसी देशों को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण

भूमिका निभा सकती है।

## महामारी, जलवायु परिवर्तन और

## युद्धों का भी असर

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम फ्रांस की सुश्री

क्लेमेंटाइन ओस्कॉनर ने खाद्य पदार्थों की हानि और

बर्बादी के मैट्रिक्स तथा कृषि एवं पर्यावरण की

स्थिरता पर इसके प्रभाव के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि महामारी, जलवायु परिवर्तन और

युद्धों का भी खाद्य पदार्थों की हानि और बर्बादी पर

गंभीर प्रभाव पड़ता है।

उन्होंने दुनिया भर में सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को

सीखने और साझा करने तथा उपभोक्ताओं के बीच

जागरूकता पैदा करने के लिए नीति बनाने पर जोर

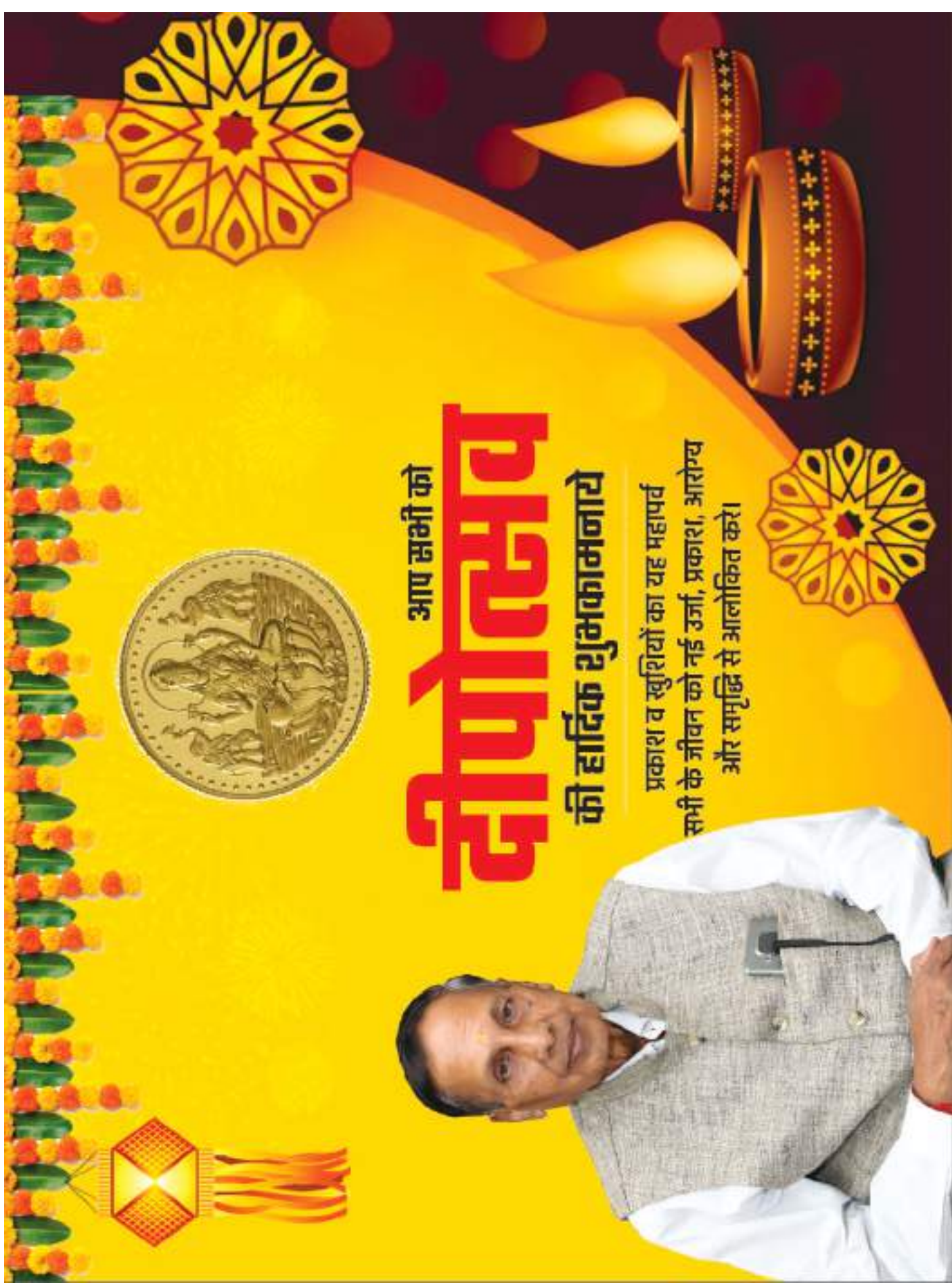
दिया। उन्होंने याद दिलाया कि 2030 तक खाद्य

पदार्थों की हानि को कम करके आधा करने के लक्ष्य

12.3 के सतत विकास को हासिल करने के लिए

केवल कुछ ही साल बचे हैं।





**आप सभी को**

# दीपोत्सव

**की हार्दिक शुभकामनायें**

प्रकाश व खुशियों का यह महापर्व  
सभी के जीवन को नई उर्जा, प्रकाश, आरोग्य  
और समृद्धि से आलोकित करे।

## क्या आप अपना खुद का व्यापार स्थापित करना चाहते हैं ?

मध्य भारत की तेजी से बढ़ती हुई रिटेल चैन  
आउटलेट बीज भंडार की फ्रेंचाइजी ले  
और बने अपनी दुकान के मालिक

**बीज भंडार की फ्रेंचाइजी लेने के लिए संपर्क करें।**

**जैन बीज भंडार एग्रो. प्रा. लि, खरगोन मोबा. 8305103633**

**बीज भण्डार**<sup>TM</sup>



उन्नत खेती के उत्तम बीज

स्वामी विवेक जैन, प्रकाशक विवेक जैन, मुद्रक कैलाश महाजन द्वारा गोपाल प्रिंटिंग प्रेस, तिलक पथ, खरगोन से मुद्रित एवं 26/1, विवेकानंद कॉलोनी, वाई नंबर 5, खरगोन से प्रकाशित, संपादक विवेक जैन। RNI No. MP/HIN/2022/85285, मोबा. नं. 98262 25025, 94254 89337 (समस्त प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र खरगोन रहेगा)।